## महत्वपूर्ण एवं खास

### एमएलए के बढ़ेंगे दैनिक भत्ते, राज्यपाल ने दी मंजूरी

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के विधायकों का दैनिक भत्ता बढ़ाने वाले संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नगर पालिका अधिनियम में किए गए संशोधन को भी राजभवन की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि दिसंबर में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान विधायकों का दैनिक भत्ता दो हजार रुपये करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया था। राजभवन से जारी सूचना के अनुसार राज्यपाल ने इसी महीने की एक तारीख को इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। राज्यपाल ने नगर पालिक अधिनियम में किए गए संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षण प्रणाली से कराने के साथ ही जातिगत आरक्षण के मादपंड में बदलाव किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।

### अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाई, खनिज विभाग की टीम ने 12 हाईवा किया जब्त

**रायपुर (आरएनएस)।** राजधानी रायपुर में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान 12 हाईवा जब्त किया है। जब्त हाईवा वाहनों को संबंधित थानों में सुपुर्द किया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी कार्रवाई निरंतर की जाए, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन और उप संचालक खनिज के निर्देशानुसार बीती रात अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम ने सुपरवाइजर सुनीलदत्त शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाकर 12 हाईवा रेत को जब्त किया गया। यह कार्रवाई रायपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई, जिसमें उपरवारा, नयापारा, अभनपुर और खरोरा शामिल हैं। जब्त हाईवा वाहनों को संबंधित थानों में सुपुर्द किया गया है। खनिज विभाग की टीम ने रायपुर के विभिन्न मार्गों पर चल रहे जांच अभियान के दौरान यह कार्रवाई की।

### अंतरक्षेत्रीय क्रिकेट स्पर्धा में मड़वा की टीम ने रचा इतिहास

**कोरबा- जांजगीर ।** पॉवर कंपनीज अंतरक्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस) मड़वा की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया है। डीएसपीएम कोरबा पूर्व में आयोजित इस स्पर्धा में एबीवीटीपीएस मड़वा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट से लौटकर टीम के कप्तान दिनेश मेश्राम और खिलाडिय़ों ने मुख्य अभियंता एचएन कोसरिया से मिलकर उन्हें ट्रॉफी भेंट किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता कोसरिया ने टीम के खेल भावना की प्रशंसा की। साथ ही खिलाडिय़ों को भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। पॉवर कंपनीज अंतरक्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह (डीएसपीएम) कोरबा पूर्व को मिली थी। 7 से 13 जनवरी तक आयोजित इस स्पर्धा के फाइनल मैच में मड़वा की टीम का मुकाबला रायपुर सेंट्रल के साथ हुआ। रायपुर सेंट्रल ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर मड़वा के सामने 130 रन का लक्ष्य दिया था। इसे मड़वा की टीम ने शानदार पारी खेलते हुए 7 विकेट खोकर 19.4 ओवर में पूरा कर लिया। मड़वा के खिलाड़ी चंद्रशेखर पटेल को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। खिलाड़ी पटेल ने अच्छी पारी खेलते हुए 48 रन बनाए और तीन ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा सचिव केके. टोप्पो, वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ अभय मिश्रा, कल्याण अधिकारी आरएस टेकाम समेत खिलाड़ी उपस्थित रहे।

# ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ में आ रही परिवहन क्रांति

**रायपुर | आरएनएस**

भारत सरकार ने अपनी समग्र नीति मे विभिन्न प्रकार की योजनाओं और पहलों के माध्यम से देश में एक डिजिटल और हरित भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर रही है. इसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री ई-बस सेवा जिसे भारत के विभिन्न हिस्सों में लागू किया गया है. दूरदर्शी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ भी इस क्रांति का हिस्सा बना है. इस योजना से छत्तीसगढ़ में परिवहन क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

ई-बस सेवा के पीछे का लक्ष्य है सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. इलेक्ट्रिक बसों की सेवा प्रदूषण की बढ़ती समस्या का एक बड़ा समाधान बनने के अलावा, यह सेवा सस्ती, सुलभ और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी एक प्रयास है, जो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प प्रस्तुत करती है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसों के साथ कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति हुए हैं. राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी और जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बना कर ईको फ्रेंडली बसें चलाई जा रही हैं.

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है. 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है.

इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति मिली. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय और संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा.

ई-बसें प्रदूषण मुक्त होती हैं क्योंकि ये बैटरी से चलती हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है. इनका उपयोग करने से न केवल ग्रीनहाउस गैसों में कमी आएगी, बल्कि यह वायु गुणवत्ता में सुधार भी होगा.

डीजल और पेट्रोल से चलने वाली बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों में अत्यधिक ऊर्जा दक्षता होती है और ये कम ऊर्जा खर्च करती हैं, ईंधन की बचत होती है और खर्चों में कमी आती है. हालाँकि, इन बसों की खरीद पर अधिक लागत आती है, लेकिन इसके संचालन की लागत में डीजल और पेट्रोल से मुक्त होने की वजह से कम होती है.

साय सरकार इस बात के लिए भी चैतन्य है कि ई-बस से राज्य सरकार को दीर्घकालिक लाभ भी होगा. सुडा ने रायपुर में बस सेवा शुरु करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की. इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है. सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए.

दुर्ग-भिलाई में ई-बसों के बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा ने जारी की है. इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है. वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है. बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है. इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है. बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

इलेक्ट्रिक बसें एडवांस्ड बैटरी के इस्तेमाल से लंबी दूरी तक बिना रुकावट यात्रा कर सकती है. ये बसें स्मार्ट चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से चार्ज की जा सकेंगी जो भविष्य में यात्री परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी. ई-बस सेवा से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं. इन बसों के संचालन, मरम्मत और चार्जिंग स्टेशन की देखभाल के लिए नए लोगों की ज़रूरत होगी.

## जिले के 757 हितग्राहियों को मिला मालिकाना हक : कृषि मंत्री नेताम ने स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड किया वितरित

**रायपुर**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वर्चुअल रूप से स्वामित्व योजना के तहत देशभर के लगभग 50 हजार ग्रामों में 65 लाख अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी बाजारपारा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम स्वामित्व योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा व जिला पंचायत सीईओ रेना जमील, जनपद उपाध्यक्ष भानुप्रकाश दीक्षित, गणमान्य नागरिक, स्वामित्व योजना लाभार्थी व आम नागरिक उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 05 साल पहले स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। बीते 05 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। आज योजना से कई लोगों को अपने घर का प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। इसके लिए उन्होंने बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में पानी, स्वास्थ्य संकट, महामारी जैसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने प्रॉपर्टी अधिकार की चुनौती रही है। इस चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारी सरकार ने प्रॉपर्टी के लिए सबका विकास करते हुए स्वामित्व योजना का संचालन शुरू किया। इस योजना से लाभार्थियों के जीवन में बदलाव आया है। बैंक से लोन लेने में मदद मिल रही है। इस योजना से लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी है। कई लाभार्थियों ने स्वामित्व योजना का लाभ मिलने से कानूनी संपत्ति के आधार पर लोन लेकर छोटा-मोटा व्यापार शुरू किया है। इनके लिए प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन चुकी है। शासन द्वारा आमनागरिकों के लिए योनजाएं भी संचालित की जा रही है। उज्ज्वला गैस, नल-जल, बैंकों में खाता हो या आयुष्मान मंदिर से गांव के लोग जुड़ने लगे।

ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कार्यक्रम में स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले के 757 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री नेताम ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्र दिया गया साथ ही लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्लानिंग कर योजना लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत स्वामित्व योजना में लोगों के पास अपने घर की प्रॉपर्टी होगी और बैंकों से लोन भी आसानी से मिल जाएगा। अब हर गरीब व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र रहेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री नेताम ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति भारत का शपथ भी दिलाया।

## अलग-अलग सडक़ हादसों में चार की गई जान

**रायपुर (आरएनएस)।** अलग-अलग सडक़ हादसों में चार लोगों की जान चली गई। मामले में पुलिस ने सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पहला हादसा माना बस्ती के एसीसी सीमेंट के पास हुआ है। बताया जाता है कि मृतक यादोराम साहू 60 वर्ष अपनी पुत्र नीरज साहू व विकास साहू के साथ बाइक से कहीं जा रहा था, तभी कार क्रमांक सीजी 10 एफ 8999 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे यादोराम की मौत हो गई। मामले में माना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। वहीं दूसरे मामला मेन रोड सेमरिया में हुआ, जहां ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 एमआर 7037 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक्टिवा को टक्कर मार दिया। जिससे एक्टिवा सवार अनिल यादव 30 वर्ष निवासी बलौदाबाजार की मौत हो गई। मामले में विधानसभा पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। इसी तरह तीसरे मामला आरंग थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे 53 स्थित ढिल्लन ढाबा शौचालय के पास इंडेन गैस टैंकर क्रमांक टीएन 88-5670 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रोड क्रास कर रहे दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बबन राव लाहने 75 वर्ष और घनश्याम यादव 40 वर्ष की मौत हो गई। मामले में आरंग पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

## शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर एक मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू

**रायपुर | आरएनएस**

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। यहां आरटीई की एक भी सीट खाली न रहे इसके लिए शिक्षा विभाग ने दो माह पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट करने को कहा है। निजी स्कूलों ने सीटों की जानकारी अपडेट करना शुरू कर दिया है। जारी निर्देश के मुताबिक शिक्षा अधिकारी 31 जनवरी तक स्कूलों की प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे. 1 से 29 फरवरी के बीच स्कूलों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा और शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों की संख्या अपडेट की जाएगी.

1 मार्च से आवेदन करें, चयन लॉटरी से होगा

सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों की संख्या अपडेट की जाएगी। फिर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केजी-1 और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया 1 से 31 मार्च तक शुरू की जाएगी। इस दौरान 17 मार्च से 25 अप्रैल तक नोडल अधिकारी मिले दस्तावेजों की जांच करेंगे. 1 और 2 मई को लॉटरी के जरिए सीटों का आवंटन किया जाएगा. इसके बाद लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों को चिन्हित स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया 5 से 30 मई तक जारी रहेगी. यदि सीटें खाली रहती हैं तो दूसरे चरण की प्रक्रिया होगी।

## फरार गांजा तस्कर गिरफ्तार, चक्रधरनगर पुलिस ने सक्रियता से सक्ती में दबोचा

**रायगढ़**

चक्रधरनगर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक फरार आरोपी को सक्ती जिले के बोईरडीह से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।

घटना की पृष्ठभूमि 13 जनवरी की है, जब चक्रधरनगर पुलिस ने वीआईपी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए चिटकाकानी क्षेत्र में नाका लगाया था। इसी दौरान, एक मोटरसाइकिल सवार ने चेकिंग प्वाइंट से पहले ही वाहन मोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस को शक हुआ। भागने के प्रयास में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक को सतर्क पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पकड़े गए युवक, कमलेश साहू (30 वर्ष), ने अपने बैग में 7.220 किलोग्राम गांजा होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने गांजा, जिसकी कीमत रु.86,640 आंकी गई, और फरार आरोपी राजकुमार साहू का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। आरोपी कमलेश साहू को अप.क्र. 20/2025 धारा 20 बी, 29 एनडीपीएस एक्ट में उसी दिन गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। फरार आरोपी राजकुमार साहू की तलाश में थाना प्रभारी प्रशांत राव की अगुवाई में पुलिस टीम ने कई बार उसके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिरों को सतर्क कर रखा गया था, जिनकी सूचना पर आज सुबह पुलिस ने राजकुमार साहू (25 वर्ष) को सक्ती जिले के उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने उड़ीसा से गांजा लाने और इसे अपने साथी कमलेश के साथ बेचने की योजना स्वीकार किया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्लेटिना सीजी 11 एए 4124 बरामद किया गया है।

थाना चक्रधरनगर में आरोपी राजकुमार साहू के खिलाफ एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध अपराध में रिमांड पर जेल भेज दिया है।

फरार आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी और हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

## हेलमेट जागरूकता रैली में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी

- नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति किया प्रेरित

**रायपुर**

36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत यातायात जागरूकता अभियान जिले में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों एवं शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

सरगुजा जिला प्रवास के दौरान आज ओपी चौधरी ने हेलमेट जागरूकता रैली में सहभागिता की और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने पीजी कॉलेज ग्राउंड से सर्किट हाउस तक बाइक रैली में स्वयं शामिल होकर आम नागरिकों को सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी बाइक चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की।

रैली को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जनहानि से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। हेलमेट न पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने युवाओं और दोपहिया वाहन चालकों से विशेष रूप से अपील की कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और हेलमेट पहनने की आदत डालें।

मंत्री चौधरी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने प्रशासन, पुलिस विभाग, सामाजिक संगठनों और आम जनता से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर क्षेत्रिय विधायक राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी योगेश पटेल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

# कोरबा में मिले किंग कोबरा की प्रजाति, एक बूंद जहर ले लेता है जान

**कोरबा | आरएनएस**

छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाए जाने वाले किंग कोबरा की प्रजाति जानने के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। वैश्विक स्तर पर हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि किंग कोबरा की आफियोफैगस हन्ना के साथ ही तीन और प्रजातियां आफियोफैगस कलिंगा, आफियोफैगस साल्वाटाना, आफियोफैगस बंगारस प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

कोरबा में मिलने वाले किंग कोबरा के प्रथम दृष्टया आफियोफैगस हन्ना या आफियोफैगस कलिंगा प्रजाति के होने की संभावना है। हालांकि, टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कोरबा का किंग कोबरा चारों प्रजातियों में से कोई एक है या फिर कोई नई प्रजाति है।

साल 2014 में कोरबा जिला के बताती गांव में रहने वाले एक किसान की बाड़ी में किंग कोबरा पहली बार नजर आया। इसके बाद कोरबा के कई अन्य स्थानों पर कोबरा मिलने लगे। साल 2021 में मदनपुर गांव में सबसे लंबा करीब 18 फीट लंबा कोबरा मिला।

नोवा नेचर व अन्य संस्थाओं ने मिलकर इलाके में अब तक 250 से अधिक किंग कोबरा की गणना की है। सर्प मित्र और सर्वे दल के सदस्य जितेंद्र सारथी ने बताया कि कोरबा वन मंडल के साथ सूरजपुर जिले की सरहद तक कोबरा के रहवास के निशान मिले हैं। बताती क्षेत्र के जंगल को कोबरा रहवास के रूप में विकसित किया जा रहा है।

**कहां पाई जाती है कौन सी प्रजाति**

आफियोफैगस हन्ना: अब तक इसे ही किंग कोबरा की एकमात्र प्रजाति माना जाता रहा है, जो पूर्वी पाकिस्तान उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत में भी पाया जाता है।

आफि योफैगस कलिंगा: इसे भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली प्रजाति के तौर पर दर्शाया गया है।

**विष इतना शक्तिशाली कि हाथी को भी मार गिराए**

नोवा नेचर संस्था के अध्यक्ष एम सूरज का कहना है कि कोबरा के अनुकूल कोरबा जंगल का वातावरण है। कोबरा 20 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। कुछ कोबरा के विष इतना शक्तिशाली होता है कि वह हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार कर गिरा सकता है।

ओडिशा और बस्तर क्षेत्र के पूर्वी घाट में किंग कोबरा की मौजूदगी पाई गई है। कोरबा में इनकी संख्या अच्छी खासी है। इन जगहों पर सर्पदंश यानी सांपों के काटने के मामले भी ज्यादा मिलते हैं।